ऐतिहासिक दुकान को बंद कराकर ही मानी नौकरशाही

वाई.के. रज्जन

सरकारी महकमे की दादागिरी अच्छे खासे बिजनेस और धरोहर को नष्ट कर सकती है। दिल्ली के चांदनी चौक में घंटेवाला मिठाई की दुकान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जो पिछले दो महीने से बंद पड़ी है। इसके मालिक सुशांत जैन का कहना है कि वो अब इसे नहीं खोलेंगे। हुआ यह कि इस दुकान पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन् 2000 से लगातार इस ऐतिहासिक मिठाई की दुकान के पीछे पड़ा हुआ था। इस दुकान पर इतने मुकदमे और चालान कर दिए गए कि इसके मालिक को रोजाना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से ही फ़ुरसत नहीं मिलती थी। ऐसे में उन्होंने दुकान को बंद करने में अपनी भलाई समझी।

हालांकि मीडिया में पहले यह खबर आई थी कि लोगों की खाने की आदतें बदल चुकी हैं और इसके परंपरागत ग्राहक यहां आने से कतराने लगे थे। इसलिए इस दुकान को बंद किया गया। लेकिन इसकी असली वजह अफ़सरों की हरामखोरी व भ्रष्टाचार ही रही। अगर इस दुकान को बंद होना होता तो इसके बगल में 20 साल पहले खुली हल्दीराम की दुकान के बाद ही इसे बंद हो जाना चाहिए था लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं घंटेवाला के आसपास ही कई मशहूर मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट हैं लेकिन इसकी बिक्री पर कभी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अफ़सरों के आगे इस दुकान को भी झुकना पड़ा। हालांकि जुलाई में जब इस दुकान को बंद किया जा रहा था तो दिल्ली में आम आदमी के नाम पर आई अरविंद केजरीवाल की सरकार इसे रुकवा सकती थी लेकिन उसके भी कान भी जूं नहीं रेंगी। यह अपने आप में बड़ा मजाक है कि इसके आसपास हल्दीरामए मैकडॉनल्ड सहित कई फ़ूड चेन की दुकानें हैं लेकिन दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इन दुकानों में कभी कोई प्रदूषण नजर नहीं आया। सिर्फ चांदनी चौक ही क्यों, गली पराठे वाली में क्या पराठे की मशहूर दुकानों को इसलिए हटा दिया जाए कि वह प्रदूषण फैलाती है। दिल्ली में इतनी सारी फैक्ट्रियां अपना मलबा, कूड़ा यमुना में डालती हैं लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इनका प्रदूषण नहीं दिखाई देता है।

बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि मुगलकालीन दिल्ली में 225 साल पहले जब शाह आलम का शासन था, तब राजस्थान से आए सुखराम जैन ने सन् 1790 में यह दुकान खोली थी। इससे पहले वह तांबे के बर्तन में मिठाई रखकर और सिर पर लादकर बेचते थे। चलते हुए वह एक घंटी भी बजाते थे। यही उनकी पहचान बन गई। जब उनकी बिक्री बढ़ी तो उन्होंने चांदनी चौक में यह दुकान खोली। 1911 में घंटेवाला हलवाई और करीम होटल को दिल्ली के गैजटियर में शामिल किया गया और इन्हें दिल्ली की पहचान बताया गया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि घंटेवाला हलवाई सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल था। आसपास बड़ी मुस्लिम आबादी होने की वजह से ईद के त्योहार पर घंटेवाला की मिठाई न हो तो ईद ही नहीं मनती थी। लोगों की लाइन लगती थी और नंबर आने पर लोग मिठाई खरीदते थे। मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब दिल्ली आने पर यहां खास तौर पर मिठाई खाने आते थे। इंदिरा गांधी का एक फ़ोटो घंटेवाला मिठाई के डिब्बों के साथ देखा जा सकता है। यह मिठाई इंदिरा गांधी ने कोरिया मिशन पर तैनात फ़ौजियों के लिए भेजी थी। कई मशहूर हस्तियों और देशों के प्रशंसापत्र अब इस दुकान मालिक के पास ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गए हैं।

साहब लोगों का नया फ़र्जीवाड़ा

वाई.के. रज्जन

हरियाणा में अपने ठाठ के लिए नौकरशाही कुछ भी कर सकती है। अगर आप किसी आईएएसए एचसीएस या जूडिशल मैजिस्ट्रेट के घर जाएंगे तो पाएंगे, तमाम सरकारी कर्मचारी इन अफ़सरों और इनके बच्चों की सेवा में दिन.रात लगे रहते हैं। इनकी ड्यूटी किसी सरकारी दफ़्तर में होनी चाहिए लेकिन ये लोग आपको अफ़सर के घर चाकरी करते मिल जाएंगे। अभी तक ये सब काम बिना नियम कानून चल रहा था। अब नौकरशाही ने बाकायदा इस संबंध में एक घोषणा कराकर इसे कानूनी जामा भी पहना दिया।

इसी महीने की 7 तारीख को हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी आईएएसए एचसीएसए जूडिशल अफ़सर और सभी विभागों के हेड अपने घर पर चपरासी रख सकेंगे। इस चपरासी का वेतन सरकार देगी। तमाम कानूनी पचड़े से बचने और भविष्य में इस आदेश को चुनौती न दी जा सके, इसमें एक शर्त और जोड़ दी गई है कि ऐसा करने वाले अफ़सर के घर पर इसके बाद कोई कर्मचारी फिर काम नहीं करेगा।

अब आइए नजर डालते हैं कि इस आदेश के लागू होने से पहले किस अधिकारी के घर कितने कर्मचारी बेचारे सेवादारी में रहते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक डीसी के घर पर चार कर्मचारी, एडीसी के घर 2, हुडा प्रशासक के घर 4 कर्मचारी, संपदा अधिकारी के घर 1 कर्मचारी, नगर निगम कमिश्नर के घर 6 कर्मचारी, नगर निगम के विभिन्न बड़े अफ़सरों के घर 1 से 2 कर्मचारी, तहसीलदार के घर 1 कर्मचारी, एसडीएम के घर 1 कर्मचारी, सिटी मैजिस्ट्रेट के घर 1 कर्मचारी ड्यूटी बजाते हैं। बिजली विभाग के आला अफ़सर भी इसमें शामिल हैं, जिनके घर लाइनमैन तक ड्यूटी बजाते नजर आते हैं। इनमें ज्यादातर माली, रेडक्रास से जुड़े कर्मचारी, बेलदार, दिहाड़ी वाले कर्मचारी होते हैं। इनका वेतन इनके विभागों से मिलता है लेकिन ड्यूटी इनकी साहब के घर होती है। उदाहरण के तौर पर फ़रीदाबाद के टाउन पार्क में जितने मालियों की ड्यूटी लगती है अगर उनके रेकॉर्ड की जांच की जाए तो पता चलेगा कि टाउन पार्क आज इतना बदहाल क्यों है। यहां के माली अपने साहब के घर पर जब ड्यूटी बजाएंगे तो टाउन पार्क में वे क्यों जाएंगे। इसी तरह तमाम विभागों का हाल है। जिस भी अधिकारी को सरकारी कार व जीप मिली हुई है वह अपने विभाग के किसी न किसी कर्मचारी की ड्यूटी अपने घर लगवा लेता है।

नया आदेश इस संबंध में हो रही आलोचनाओं को दबाने के लिए जारी किया गया है। इस आदेश से सरकारी अधिकारी यह कहने की स्थिति में आ गए हैं कि अब तो उन्हें सरकार की तरफ से यह सुविधा मिल गई है लेकिन इस कारण हरियाणा सरकार के खजाने पर लाखों का जो बोझ पड़ेगा, उसकी आड़ में ये लोग अपनी करतूत छिपा लेंगे।

फ़रीदाबाद, गुड़गांव में इतनी आरडब्ल्यूए बनी हुई हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने इलाके के पार्क को सुधरवाने के लिए मालियों की ड्यूटी उस सरकारी पार्क में लगवा लें। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है कि वे इस मांग को लेकर कोई धरना.प्रदर्शन कर सकें। इतना भी साहस नहीं कि यह सार्वजनिक रूप से पूछ सकें कि उनके इलाके में जिस माली या लाइनमैन की ड्यूटी है, वह साहब के घर पर क्यों हैं.....इन सब बातों के लिए जनता भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। वह सुविधाभोगी और डरपोक है। उसे अपना घर साफ चाहिए, जिसके लिए उसने ऐसे लोगों की सेवाएं ले रखी हैं। उसे अपने इलाके के पार्क, स्ट्रीटलाइट, सीवर, सड़क से मतलब नहीं है। वो आरडब्ल्यूए वालों को चंदा देकर अपना पिंड छुड़ा लेती है लेकिन सवाल नहीं पूछ पाती कि उनके जो मूल काम हैं वो लोग उसे क्यों नहीं कर रहे हैं।

और व्यापमं के बाद अब डीमेट घोटाला

व्यापमं के अलावा मध्यप्रदेश में अब डेंटल एंड मेडिकल एंट्रेंस टैस्ट (डीमेट) घोटाला सामने आया है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में मैंनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने के लिये एसेसियेशन फ़ॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज (एमपीएमडीसी) डीमेट कराती है। इनमें 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई, 43 प्रतिशत सीटें डीमेट और 42 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे से यानी पीएमटी के जरिए भरी जाती है।

मध्यप्रदेश में 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज व 14 प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं। इसमें एमबीबीएस की 900, एमडी व एमएस की 222, बीडीएस की 1320 व एमडीएस की 117 सीटें हैं। सोचने वाली बात है कि मोटा मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से खोले गये इन निजी शिक्षण संस्थानों का ध्येय वाक्य हर कीमत पर पैसा इकट्ठा करना है। छात्रों से मोटी फ़ीसों के अलावा ये सीटों को बेचकर अकूत मुनाफ़ा अर्जित कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि डीमेट में तो गड़बड़ी होती ही थी, सरकारी कोटे की सीटों को भी गलत तरीके से बेचा जाता था।

निजी कॉलेज डमी उम्मीदवारों का चयन डीमेट पीएमटी में करवा देते थे। बाद में इन सभी उम्मीदवारों की सीटें सरेंडर करवा दी जाती थीं। फ़िर खाली सीटों को वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों से भरने के बजाय बेच दिया जाता था। यह मामला भी व्यापमं की तरह हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसकी जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग हो रही है।

यह घोटाला तब सामने आया जब व्यापमं में निदेशक रहे और वहां से रिटायरमेंट के बाद डीमेट के कोषाध्यक्ष रहे योगेश उपरीत की गिरफ़्तारी हुई। वह दस साल तक डीमेट के परीक्षा नियंत्रक भी रहे। उपरीत को व्यापमं की प्रि पीजी परीक्षा में जबलपुर के एक बड़े डॉक्टर की बेटी को फ़र्जी तरीके से पास कराने के आरोप में 3 जून को गिरफ़्तार किया गया। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के मंत्री व कुछ बड़े अफ़सर इसमें लिप्त हैं। इस घोटाले के 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़े होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। उपरीत ने बयान देकर कहा है कि हर साल लगभग 1500 सीटों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले अपनी मर्जी से भर्ती करते थे।

इसमें बीडीएस, एमबीबीएस, एमएस और एमडी की सीटें शामिल हैं। एक उम्मीदवार से 50 लाख से लेकर डेढ करोड़ तक लिया जाता रहा। निजी मेडिकल कॉलेज़ों में वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2013 तक 721 छात्रों को दिये गये प्रवेश की जांच करने को कहा गया है। ये 721 सीटें निजी कॉलेजों ने खुद ही काउंसलिंग कर भर दी थीं।

इस प्रकार इन प्राइवेट कॉलेजों ने न सिर्फ़ मोटी फ़ीसों के जरिये बल्कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर लूट का साम्राज्य खड़ा किया है। जब लूट के उद्देश्य से निजी शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं तो पूंजी अपना चरित्र यहां भी दिखायेगी। शिक्षण संस्थान, उच्च गुणवत्ता आदि-आदि पवित्र बातें करते हुए ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहे हैं। शिक्षा के निजीकरण के जरिये निजी पूंजी को मिली छूट ने शैक्षिक संस्थानों को और खूंखार तथा मारक बना दिया है। पूंजीपति किसी भी कीमत पर संपत्ति में वृद्धि चाहता है। उसके लिये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह शैक्षिक संस्थान चला रहा है या अस्पताल। हर जगह वह पूंजी का हाहाकार ही कायम करेगा।

जिनके मेडिकल एंट्रेस रद्द किये गये

2013	439
2012	333
2011	98
2010	90
2009	85
2008	42

-परचम

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 सितम्बर 2015 के अंक में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। नरेन्द्र मोदी की तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वाह वाही लूटने के लिये घोषणाएं करते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। इसका नवीनतम उदाहरण है हरियाणा के हर ज़िले में महिला पुलिस थाने खोलना और खट्टर इसे हरियाणवी महिलाओं के लिए एक नायाब तोहफ़ा बताकर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिसका 'खबर दार महिला पुलिस थाना-किसके लिये' व 'महिला थाना छलावे को बता रहे तोहफ़ा' लेखों में खुलासा किया गया है।

भारत के किसी भी अन्य राज्य (तमिलनाडू को छोड़कर) ने महिला थानों की स्थापना नहीं की है। गौरतलब है कि एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार हरियाणा राज्य के हर ज़िले में महिला थानों की स्थापना के बावजूद महिला थानों में पीड़िता की शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही। गुड़गांव, पानीपत व यमुनानगर में महिला पुलिस थानों का रवैया पीड़िता के ही विरुद्ध रहा।

यमुनानगर महिला पुलिस थाने में जब कोई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उस इलाके के लोग थाना शहर जगाधरी पहूंचे तो वहां की पुलिस ने फ़ौरन आरोपी के खिलाफ़ केस दर्ज़ कर लिया। इसके अतिरिक्त एक और चौकानेवाली घटना है जींद महिला थाने की जहां पर तैनात एक महिला पुलिस हैड कांस्टेबल ने वहीं थाने में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जहर खाने से पहले महिला हैड कांस्टेबल ने एक स्यूसाईड नोट लिखा जिसमें उसने महिला थाने की एसएचओ और एसपी समेत 4 पर गंभीर आरोप लगाए, परंतु उस स्यूसाईट नोट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्पष्ट है कि महिला थानों की स्थापना की अवधारणा तमिलनाडू की तरह फ़्लॉप सिद्ध हो रही है। इसलिये केरल की तर्ज़ पर हर पुलिस थाना चौकी में महिलाकर्मियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जानी चाहिए।

'मोदी व खट्टर के इन्तज़ार में खड़े-खड़े जंग खा रही मैट्रो' तथा 'मैट्रो की तारीख के नाम पर भद्दा मज़ाक' लेखों में एक माह से भी ऊपर चलने के लिये तैयार मैट्रो के उद्घाटनों के इन्तज़ार में लाखों दैनिक यात्रियों की परेशानी और मैट्रो रेल कम्पनी को लगभग 20-25 लाख रुपये प्रतिदिन के नुकसान का उचित विवेचन किया गया है। इसके बनाने पर हुए खर्च में मोदी व खट्टर का कोई योगदान नहीं है। यह कार्य तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हो चुका था। मोदी के फ़रीदाबाद आने पर उसके स्वागत के लिये मुख्य सड़कों पर प्रवेश द्वार बनाए गए थे। सूरजकुण्ड रोड पर एसियन अस्पताल की तरफ़ से बनाए गये प्रवेश द्वार पर बड़े-बड़े अक्षरों में फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने और फ़रीदाबाद में मैट्रो लाने के लिये मोदी को धन्यवाद दिया गया था। एसियन अस्पताल के डायरैक्टर डॉ. पाण्डे द्वारा मोदी की चापलूसी का यह एक नायाब नमूना है। गौरतलब है कि डॉ. पाण्डे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की चापलूसी किया करते थे। वास्तव में डॉ. पाण्डे भी एक व्यवसायी है और और वह भी हर व्यवसायी/उद्यमी की तरह उस समय की सरकार की चापलूसी कर मुनाफ़ा कमाने का प्रयास करते हैं। लेख 'भाजपा ने दिखलाई राज की गुंडागर्दी दलितों की पिटाई भी की और मीटिंग भी नहीं होने दी' से स्पष्ट है कि मोदी की छत्रछाया में देश में एक ऐसा आक्रामक माहौल बनाया जा रहा है कि जो संघ की विचारधारा का विरोधी है, संघ परिवार उसे देशद्रोही करार करके कुचलने का प्रयास करता है। एक अन्य लेख 'लाल किले से बरसा मोदी का साम्प्रदायिकतावाद और जातिवाद-अटाली और भगाना के विस्थापित कब बसेंगे! मोदी सरकार व संघ परिवार की साम्प्रदायिकता व जातिवाद की नीति का सांगोपांग खुलासा किया गया है। साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिये दलित, मज़दूर, किसान व प्रगतिशील लोग़ों को एकजुट होना होगा।

लेख 'दंगाइयों को कोई अदालत दोषी नहीं ठहरा सकती, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी' द्वारा जस्टिस बी एन श्री कृष्णा रिपोर्ट के संदर्भ में आतंकवादी षडयंत्र, दंगों में आरोपित मुस्लिम आतंकवादियों को सज़ा देने व हिंदू अतिवादियों से जुड़े आरोपियों को जमानत मिलने का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सटीक विश्लेषण किया गया है। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घोषित अभियुक्त शिवसेना प्रमुख बालठाकरे को वर्ष 2012 में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना देश की व्यवस्था पर गहरी चोट है। इससे देश की न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगता है।

स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुकी/मियां की जूती मियां के सिर' मोदी द्वारा सब्ज़ बाग दिखलाकर नौजवानों को बरगलाने और गुजरात में पटेलों के आरक्षण आन्दोलन को लेकर भड़की हिंसा के संदर्भ में मोदी की अपील पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।

लेख 'हार्दिक पटेल की आड़ में संघ का एजेंडा' में गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन का सटीक विश्लेषण किया गया है। इस आंदोलन की पटकथा संघ द्वारा लिखी गई थी। हार्दिक पटेल के पिता भाजपा के नेता हैं और हार्दिक पटेल स्वयं प्रवीण तोगड़िया का अनुयायी रहा है। हार्दिक पटेल की मांग कि या तो देश में आरक्षण समाप्त करो वरना हमें भी आरक्षण दो, वास्तव में यह संघ की मांग है कि देश में आरक्षण समाप्त हो जिसका समर्थन देश का बेरोज़गार नौजवान कर रहा है जो रोज़गार न मिलने से हताश है।

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिये मोदी सरकार द्वारा धार्मिक जनगणना आंकड़े प्रकाशित करने का लेख 'धामिक जनगणना के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण' में खुलासा किया गया है। मीडिया मोदी सरकार व संघ परिवार द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को ही परोश रहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है ओर मुसलमान बढ रहे हैं। जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। पिछली सदी के आखिरी दशक में मुसलमानों की आबादी घटने की दर 3-6 प्रतिशत थी तो वहीं हिंदुओं की 2-8 प्रतिशत थी। इस प्रकार मीडिया की खबरें ग़ैर ज़िम्मेदाराना तथा एक विशेष राजनैतिक विचारधारा को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। अन्य प्रकाशित लेख भी उच्च स्तरीय व प्रशंसनीय हैं।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता